

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए./4419/2006/अलवर दयाराम व अन्य बनाम गारा सिंह व अन्य	
	<p style="text-align: center;">एकल-पीठ श्री धूकलराम कसवॉ, सदस्य</p> <p>उपस्थित:- (1) श्री ईश्वर देवडा अभिभाषक प्रार्थी (2) श्री अविनाश माथुर अभिभाषक अप्रार्थी</p> <p style="text-align: center;">निर्णय दिनांक :</p> <p>यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 230 के अन्तर्गत भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर के निर्णय दिनांक 4-7-06 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई हैं।</p> <p>2- प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अप्रार्थी संख्या 1 गारा सिंह ने उप जिला कलेक्टर तिजारा के न्यायालय में एकतरफा में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 3-2-88 को निरस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 जाब्ता दीवानी प्रस्तुत किया जिसे विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई अपने आदेश दिनांक 20-1-99 के द्वारा खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर अप्रार्थी संख्या 1 ने भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 4-7-06 के द्वारा अपील स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 20-1-99 को निरस्त कर अप्रार्थी प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 जाब्ता दीवानी को स्वीकार कर एकतरफा में पारित निर्णय दिनांक 3-2-88 को अपास्त करते हुये अप्रार्थी संख्या 1 को भी सुनवाई का अवसर प्रदान कर निर्णय पारित करने हेतु विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया। इससे व्यथित होकर यह निगरानी मण्डल के समक्ष पेश की गई है।</p> <p>3- उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस निगरानी पर सुनी गई।</p> <p>4- प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने निगरानी मीमो में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि विचारण न्यायालय में प्रार्थीगण वादीगण ने घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया था तथा उक्त वाद में प्रतिवादी को साधारण नोटिस जारी किये गये किन्तु साधारण नोटिस तामील नहीं होने पर न्यायालय के आदेश से रजिस्टर्ड एडी नोटिस जारी किये गये जो तामील होने पर भी प्रतिवादी के उपस्थित नहीं होने के कारण उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई। तत्पश्चात प्रार्थीगण वादीगण की साक्ष्य लेकर विचारण न्यायालय ने दिनांक 3-2-88 को प्रार्थीगण वादीगण का वाद डिक्री किया। अप्रार्थी प्रतिवादी</p>	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए./4419/2006/अलवर दयाराम व अन्य बनाम गारा सिंह व अन्य	
	<p>ने आदेश 9 नियम 13 जाब्ता दीवानी का प्रार्थनापत्र दिनांक 29-8-88 को प्रस्तुत किया था जो कि मियाद बाहर था। विचारण न्यायालय ने उक्त प्रकरण में यह मानते हुये कि विचारण न्यायालय की पत्रावली में रजिस्टर्ड एडी लगी हुई है जिस पर डाकघर की मोहर भी लगी है तथा तत्कालीन डाकिये का शपथ पत्र भी है। इसलिये विधिवत तामील मानते हुये विपक्षी का आदेश 9 नियम 13 जाब्ता दीवानी का प्रार्थना पत्र खारिज किया है। उनका तर्क है कि आदेश 9 नियम 13 जाब्ता दीवानी के परन्तुक में यह स्पष्ट अंकित किया गया है कि कोई भी न्यायालय एकतरफा निर्णय व डिक्री को सम्मन की तामील में की गई अनियमितता के आधार पर निरस्त नहीं कर सकता है। न्यायालय को केवल मात्र सन्तुष्ट होना है कि प्रतिवादी विपक्षी को तारीख पेशी की सूचना थी और प्रतिवादी विपक्षी के पास पर्याप्त समय था जिसमें प्रार्थीगण वादीगण के वाद का उसके विरुद्ध उपस्थित होकर जबाब दे सकता था। किन्तु अपीलीय न्यायालय ने केवल मात्र कल्पना के आधार पर आक्षेपित निर्णय पारित करने में त्रुटि की है। आदेश 9 नियम 13 जाब्ता दीवानी के प्रार्थना पत्र के साथ देरी को क्षमा करने हेतु कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया। इसलिये अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय विधि विरुद्ध होने से निरस्त योग्य है।</p> <p>5- जबाब में अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि मेरे नाम से जो सम्मन भरा गया था उस पर मेरी वल्दियत अंकित नहीं है। जब वल्दियत ही अंकित नहीं है तो फिर मुझ पर तामील कैसे हो सकती है परन्तु विचारण न्यायालय द्वारा विधि विरुद्ध तरीके से तामील मान ली गई। चावखां ने जो शपथ पत्र दिया है वह गलत है। विवादित आराजी का बेचान नये नम्बरों से किया है। साबिक खसरा नम्बर 284 से बेचान नहीं हुआ है। न्याय का यह सर्वमान्यसिद्धान्त है कि दोनों पक्षों को सुनकर ही निर्णय पारित किया जाना चाहिये। इसलिये अपीलीय न्यायालय ने एकतरफा में पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त करने में कोई विधिक भूल नहीं की है। अपने कथन के समर्थन में 2010आर बी जे पेज 197, 2008 आर बी जे पेज 355,539,2001आर आर डी पेज 262, 2018डी एन जे(3) पेज 313, ए आई आर 1973 एस सी पेज 76 की नजीरें पेश की।</p> <p>6- हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का भी बारीकी से अध्ययन किया।</p> <p>7- विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वाद पत्र के शीर्षक में एवं निर्णय दिनांक 3-2-88 में गारासिंह पुत्र नामालूम अंकित है। इसलिये यह सन्देहास्पद हो जाता है कि किसी</p>	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए./4419/2006/अलवर दयाराम व अन्य बनाम गारा सिंह व अन्य	
	<p>पक्षकार के नाम के साथ उसकी वल्लियत अंकित नहीं हो और उसकी विधिवत तरीके से तामील मान ली जावे। डाकिया चावखां ने अपने शपथ पत्र में यह अंकित किया है कि मुकदमे में अंकित प्रतिवादीगण जो कि जाति से रायसिख हैं, वे धोली पहाडी के रहने वाले हैं, की तामील असालतन की थी जो रजिस्ट्री पर उनके अंगूठा निशानी कराये थे। इन सभी लोगों को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तथा अब नजर कमजोर होने से दिखाई कम देता है। इसलिये मैंने हस्ताक्षर न करके अंगूठा लगाया है। उक्त शपथ पत्र में अंकित तथ्य भी सन्देह से परे नहीं हैं क्योंकि नजर कमजोर होने का तात्पर्य यह तो नहीं की चावखां को बिल्कुल दिखाई नहीं देता था और वह हस्ताक्षर भी नहीं कर सकता था। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि गारा सिंह को नोटिस की विधिवत तामील नहीं हुई।</p> <p>8- यहां यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि गारा सिंह ने विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 10-8-88 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें उसने यह अंकित किया है कि एक पक्षीय डिक्री दिनांक 3-2-88 की आड में वादीगण आराजी को खुर्द बुर्द व मुन्तकिल करने की धमकी दे रहे हैं। इससे भी यह स्पष्ट होता है कि यदि प्रतिवादी की विधिवत तामील हुई होती तो वह वाद का प्रतिवाद करता न कि अनुपस्थित होकर आदेश 9 नियम 13 जाब्ता दीवानी के प्रार्थना पत्र को प्रस्तुत करने की नौबत पैदा होती। इन सब तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि प्रतिवादी को सम्मन की विधिवत तामील नहीं हुई। इसलिये हम विद्वान भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते हैं और उनके द्वारा पारित निर्णय समर्थन योग्य है। इस सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने RBJ (15) 2008 page 355 (S.C.) में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि-</p> <p><u>RBJ (15) 2008 page 355 (S.C.)</u></p> <p>Code of Civil Procedure, 1908- Order 9 Rule 13- Passing of decree without service of proper notice is sufficient ground for setting aside ex-parte decree. In the absence of a notice, we do not see any justification to pass the ex-parte decree and, therefore, we are of the clear opinion that both the court below have erred in rejecting the applicatin under order IX Rule 13. In our opinion the non service of the notice was a sufficient reason to set aside the decree against the defendant no.3 (appellant herein).</p> <p>माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने RBJ (15) 2008 page 539 (H.C.) में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि-</p> <p><u>RBJ (15) 2008 page 539 (H.C.)</u></p>	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए./4419/2006/अलवर दयाराम व अन्य बनाम गारा सिंह व अन्य	
	<p><u>Code of Civil Procedure, 1908- Order 9 Rule 13- When summons were not served to the defendant- Ex-parte decree was rightly set aside after three years.</u> In this case, plaintiff-petitioners filed suit for declaration and permanent injunction in respect of disputed land which was decreed ex-parte against defendant. Defendants filed an application for setting aside ex-parte decree on the ground that proper summons were not served on them. Trial Court dismissed the application but RAA accepted the appeal filed by defendant and set aside the ex-parte decree. The Board of Revenue maintained the order of the RAA. The Hon'ble High Court held that in the light of judgments passed by all the three courts below and after considering the same, the judgments passed by the Revenue Appellate Authority as well as Revenue Board are justified in the eyes of law.</p> <p>माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने RRD 2001 page 262 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि-</p> <p><u>RRD 2001 page 262</u></p> <p>Code of Civil Procedure, Order 5 rule 17 and Order 9 Rule 13 - Service of summons - No personal service was made on defendants - Process server made report that he had visited the village and defendant has refused to accept the notice and he (process server) pasted the notice on the wall - Ex-parte proceedings and ex-parte decree - Application for setting aside ex-parte decree rejected by trial court - Appeal against - Held trial court should have got the process server produced in the court for examination on oath when defendant was denying the fact that process server had ever visited the village and had made any such report and even had pasted the notice. It is bounded duty of court to see that the party is served in accordance with law before to proceed ex-parte just on receipt of report of process server - Court should see that every provision of O.5 should be completed and accomplished in letter and spirit before ex-parte proceedings are ordered. In this case there is serious doubt about service having been effected on defendant, therefore, ex-parte proceedings, set aside .</p> <p>माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2018 DNJ (SC) page 313 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि-</p> <p>2018 DNJ (SC) page 313</p> <p>Civil Procedure Code, 1908 -O.5, R.20; O.9, R. 12, Sec. 27- Setting aside of ex-parte decree- Application rejected by the Trial Court- Summon served publishing in newspaper- No specific day, date and</p>	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए./4419/2006/अलवर दयाराम व अन्य बनाम गारा सिंह व अन्य	
	<p>time given in summons for appearance- Non-compliance of mandatory statutory requirement- No proper service of summons- Held, ex-parte decree is set aside and the trial court is directed to decide the suit on merits.</p> <p>उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण एवं विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुये प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है।</p> <p>निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">(धूकलराम कसवाँ) सदस्य</p>	

